राजधानी से प्रकाशित RNI NO. UPHIN/2010/33668

अंदाज़-ए-लखनऊ

सुल्तानपुर, हापुड़ एवं शाहजहांपुर में प्रसारित हिन्दी साप्ताहिक

वर्ष-10 अंक-35 लखनऊ, शुक्रवार 26 जून, 2020 पृष्ठ : 8 मूल्य : एक रूपया

भारत में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 15968 नए मामले

नयी दिल्ली। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 15,968 मामले सामने आए और 465 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही बुधवार को संक्रमितों की कुल संख्या 4,56,183 पर पहुंच गई जबकि मृतकों का आंकड़ा 14,476 हो गया। भारत में लगातार पांचवें दिन संक्रमण के 14,000 से अधिक मामले सामने आए और एक जून से 24 जून तक संक्रमण के मामले 2,65,648 तक बढ़े हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब भी 1,83,022 लोग संक्रमित हैं जबकि 2,58,684 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक मरीज देश छोड़कर जा चुका है। एक अधिकारी ने बताया, ''अभी तक करीब 56.71 प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।'' कोरोना वायरस से संक्रमित कुल मरीजों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। बुधवार सुबह तक जिन 465 मरीजों की मौत हुई उनमें से 248 लोगों की महाराष्ट्र में, 68 की दिल्ली में, तमिलनाडु में 39, गुजरात में 26, उत्तर प्रदेश में 19, पश्चिम बंगाल में 11, राजस्थान और

हरियाणा में नौ-नौ, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आठ-आठ, पंजाब और मध्य प्रदेश में चार-चार, तेलंगाना में तीन, जम्मू कश्मीर, ओडिशा तथा उत्तराखंड में दो-दो लोगों की मौत हुई।

केरल, बिहार और पुडुचेरी में कोविड-19 से एक-एक व्यक्ति की मौत हुई। हरियाणा में कोविड-19 से 178, कर्नाटक में 150, आंध्र प्रदेश में 119, पंजाब में 105, जम्मू कश्मीर में 87, बिहार में 56, उत्तराखंड में 30, केरल में 22 और ओडिशा में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ में 12, झारखंड में 11, असम और पुडुचेरी में नौ-नौ, हिमाचल प्रदेश में आठ, चंडीगढ़ में छह जबकि गोवा, मेघालय, त्रिपुरा और लद्दाख में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मौत के 70 प्रतिशत से अधिक मामलों में अन्य बीमारी से मरने वाले लोग शामिल हैं। संक्रमण के सबसे अधिक 1,39,010 मामले महाराष्ट्र में सामने आए। इसके बाद दिल्ली में 66,602, तमिलनाडु में 64,603, गुजरात में 28,371, उत्तर प्रदेश में 18,893, राजस्थान में 15,627 और पश्चिम बंगाल में 14,728 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के मामले बढ़कर 12,261, हरियाणा में 11,520, आंध्र प्रदेश में 10,002, कर्नाटक में 9,721 और तेलंगाना में 9,553 मामले सामने आए। बिहार में संक्रमण के 8,153, जम्मू कश्मीर में 6,236, असम में 5,831 और ओडिशा में 5,470 मामले सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 4,397 जबकि केरल में 3,451 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 2,535, छत्तीसगढ़ में 2,362, झारखंड में 2,185, त्रिपुरा में 1,259, लद्दाख में 932, मणिपुर में 921, गोवा में 909 और हिमाचल प्रदेश में 775 मरीज सामने आए। चंडीगढ़ में कोविड-19 के 418, पुडुचेरी में 402, नगालैंड में 330, अरुणाचल प्रदेश में 148 और मिजोरम 142 मामले सामने आए। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में कोविड-19 के 120 मामले सामने आए हैं। सिक्किम में अब तक संक्रमण के 79, अंडमान और निकोबार द्वीप में 50 जबकि मेघालय में 46 मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया, ''हमारे आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों से मिलान कराया जा रहा है।'' साथ ही 8,141 मामले राज्यों को सौंपे जा रहे हैं।

मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल-डीजल की कीमतें 'अनलॉक' कर दीं- राहुल

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार ने कोरोना महामारी एवं पेट्रोलियम उत्पादों के दाम को 'अनलॉक' कर दिया है। उन्होंने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने और पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से जुड़ा एक ग्राफ शेयर करते हुए ट्वीट किया, ''मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतें अनलॉक कर दी हैं।'' पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की मूल्य के संबंध में अधिसूचना के अनुसार 17 दिन तक लगातार वृद्धि के बाद बुधवार को पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। वहीं, डीजल कीमतों में देशभर में 48 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब डीजल का दाम 79.88 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं, पेट्रोल की कीमत 79.76 रुपये प्रति लीटर है।

शहरी क्षेत्र के लिए भी रोजगार गारंटी योजना लागू हो

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना लागू करने का आग्रह किया है। गहलोत ने इस संबंध में आवास एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। इसमें गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य के शहरी क्षेत्र में एक बड़े तबके की आजीविका प्रभावित हुई है। इन्हें राहत देने के लिए केन्द्र मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में बेरोजगारों को एक निश्चित समयावधि के लिए रोजगार देने वाली योजना लागू करें।

गहलोत ने शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं में राज्य को अधिक राशि आवंटित करने, योजनाओं की समयावधि बढ़ाने तथा इन योजनाओं के लिए लंबित लगभग 788 करोड़ रूपए की राशि जल्द जारी करने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को अगले दो वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने पर विचार करे तथा 31 मार्च 2022 तक इस योजना में प्रदेश को बजट उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में वायरस का सामना करने, स्वच्छता बनाए रखने एवं नियमित रूप से हाथ धोने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करना उचित होगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना की समयावधि इसी वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो गई है।

शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, केंद्रीय नेतृव से होनी है बात- शिवराज

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि वह शीघ्र ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रदेश के भाजपा नेताओं के साथ यहां बुधवार को बैठक करने के बाद चौहान ने एक बयान जारी कर कहा, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष (विष्णु दत्त शर्मा), प्रदेश के संगठन महामंत्री (सुहास भगत) और हम सब शामिल थे। एक प्रमुख विषय है मंत्रिमंडल का विस्तार। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके

बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि, उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार की तिथि नहीं बताई। चौहान ने 23 मार्च को अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगे देश व्यापी लॉकडाउन के कारण उन्होंने 29 दिन बाद 21 अप्रैल को पांच सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया था। इसमें कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी तुलसी सिलावट एवं गोविन्द सिंह राजपूत शामिल हैं।

रूस की विजय दिवस परेड में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

मास्को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि यहां 75वीं विजय दिवस परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी का भाग लेना उनके लिए गर्व की बात है। सिंह 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए रूस के रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर तीन दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को यहां पहुंचे थे। सिंह ने बुधवार को ट्वीट किया, ''1941-1945 के युद्ध में सोवियत संघ के लोगों की विजय की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मैं आज मास्को स्थित रेड स्क्वैयर में विजय दिवस परेड में शामिल हो रहा हूं।'' उन्होंने ट्वीट किया, ''मुझे गर्व है कि भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों की एक टुकड़ी भी इस परेड में शामिल हो रही है।'' भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी ने मॉस्को के रेड स्क्वायर में विजय परेड में हिस्सा लिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि रेड स्क्वैयर में सामाजिक दूरी का पूरा पालन किया जा रहा है। सिंह ने ट्वीट किया, ''मास्को में विजय दिवस परेड पर भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं की टुकड़ी की शानदार उपस्थिति मेरे लिए अत्यंत गर्व एवं प्रसन्नता की बात है।' भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों की 75 सदस्यीय टुकड़ी परेड में हिस्सा ले रही है। भारतीय दल चीन समेत कम से कम 11 देशों के सशस्त्र बल कर्मियों के साथ इस परेड में भाग ले रहा है। सिंह ने मंगलवार को रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव के साथ मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों एवं क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा की और भारत एवं रूस के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की।

बच्चों के वैज्ञानिक विधि से सूर्य ग्रहण देखकर खुशी खिले चेहरे

शाहजहाँपुर । रविवार को सूर्य ग्रहण को देखने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे वैज्ञानिक संस्था रिसर्च के अन्टा स्थित कार्यालय पर एकत्र हुए बच्चो ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाकर वैज्ञानिक विधि से दुर्लभ सूर्य ग्रहण का आनन्द लिया। इस अवसर पर रिसर्च के निदेशक डॉ. इरफ़ान ह्यूमन ने बताया कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इसे सुरक्षित विधि से देखकर वैज्ञानिक सोच को मजबूत किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना हे और पृथ्वी व सूर्य के बीच चन्द्रमा के आ जाने के कारण घटित होती है। सूर्य ग्रहण के समय किन्हीं विशेष प्रकार की किरणों का उत्सर्जन नहीं होता, बल्कि सूर्य रोज की तरह ही प्रकाश और ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। इसको लेकर व्याप्त भय, भ्रांतियां और अंधविश्वास को समाप्त करना ही हमारा उद्देश्य है, ताकि समाज में वैज्ञानिक जागरूकता का विकास हो। डॉ. ह्यूमन ने बताया कि यहां सूर्य ग्रहण की शुरूआत सुबह 10.25 मिनट पर हुई और समाप्ति 1.55 पर हुई। लेकिन सुबह बादल होने के कारण सूर्य ग्रहण प्रेमियों को निराशा हांथ लगी। दोपहर में बादलों के हटने पर सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखने को मिला और सूर्य को कटा हुआ देख कर बच्चों के चेहरे खिल गये। दोपहर 12.09 मिनट पर सूर्य ग्रहण अपने चरम पर दिखा और चारों ओर अंधेरा छा गया। बता दें यह एक दुर्लभ प्रकार का वलयकार अर्थात कुण्डलाकार सूर्य ग्रहण था, लेकिन शाहजहांपुर में आंशिक सूर्य ग्रहण ही नज़र आया क्योंकि यह क्षेत्र वलयकार सूर्य ग्रहण की बेल्ट में नहीं था।

इस अवसर पर बच्चों ने वैज्ञानिक रूप से परीक्षित मायलर फिल्टर चश्मों, पिनहोल कैमरे और एक्लिप्स व्यूअर के माध्यम से सूर्य ग्रहण को देखा। सूर्य ग्रहण देखने में इस बार महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं।

बरेली मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन की सूची में जांच के आदेश

शाहजहाँपुर। बरेली मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन की सूची में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर जांच के आदेश कर दिए गए है। बरेली मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई जिसके सम्बंध में एमएलसी अमित यादव की शिकायत पर कमिश्नर ने जांच के निर्देश दिए थे। इस परिपेक्ष में कमिश्नर ने निर्वाचन क्षेत्र के सभी जिला विद्यालय निरीक्षको को शिक्षकों के नाम मतदाता सूची से पृथक करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए है। ज्ञात हो कि विधान परिषद सदस्य ने कमिश्नर रणवीर प्रसाद से शिकायत की थी कि निर्वाचन में गड़बड़ी कराने के मकसद से तमाम ऐसी संस्थाओं के शिक्षकों को सूची में जोड़ लिया गया है। जिनकी कोई मान्यता ही नहीं है बरेली मुरादाबाद मण्डल में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षकों को सूची में शामिल किया गया है। शिकायत पत्र में उन्होंने कहा यह मामला उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के पास भी भेजा था। लेकिन कुछ अधिकारियों के दबाव में जांच को दवा लिया गया था। आज इसी परिपेक्ष में कमिश्नर ने निर्वाचन सूची में जालसाजी करने वालो के विरुद्ध सभी निर्वाचन क्षेत्र के जिला विद्यालय निरीक्षकों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। इस प्रक्रिया में बरेली मुरादाबाद क्षेत्र से सपा एमएलसी संजय मिश्रा का सहयोग रहा।

वन विभाग टीम ने पकड़ी बगैर परमिट चोरी की लकड़ी

शाहजहाँपुर। थाना कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला किला निवासी एक लकड़ी के ठेकेदार द्वारा बगैर परमिट चोरी से लकड़ी काटकर बेचने जा रहा था तभी मुखबिर ने डीएफओ को सूचना दी कि एक पिकअप में आम व शीशम की लकड़ी अबैध कटान द्वारा लाई जा रही है जिसकी बिक्री शाहजहांपुर के आर सी मिशन थाना क्षेत्र के डाबर की आरा मशीन पर होनी है फिर डीएफओ आदर्श कुमार ने एक सक्रिय टीम लकड़ी पकड़ने के लिये लगा दी। टीम ने बहुत ही सूझबूझ के साथ लकड़ी से लदी पिकअप को शाहजहांपुर के थाना रामचन्द्र मिशन क्षेत्र स्थिति एक आरा मशीन के गेट पर धर दवोचा तभी मौके पर एक लकड़ी ठेकेदार भी पहुंच गया टीम ने ठेकेदार से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि यह लकड़ी हमारी है टीम ने जब उससे कटी हुई लकड़ी का परमिट मांगा तो उसने परमिट दिखाने में असमर्थता दिखाई तो टीम ने उसको भी पकड़ लिया। लकड़ी पकड़ने वाली टीम मे के पी सिंह चन्द्र पाल सिंह मुकेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे।

विधायक रोशनलाल वर्मा की पहल पर रेप के आरोपी प्रभारी मंडी सचिव निलंबित

शाहजहाँपुर। रेप के आरोप में घिरे चल रहे तिलहर मंडी के प्रभारी सचिव अशोक दीक्षित के खिलाफ विधायक रोशन लाल वर्मा की शिकायत पर एक्शन हो गया। विधायक की शिकायत का संज्ञान लेकर मंडी परिषद के निदेशक ने अशोक दीक्षित को निलंबित कर बदायूं भेज दिया। तिलहर से भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेन्द्र प्रताप सिंह को पत्र देकर बताया था कि तिलहर मंडी परिषद के प्रभारी सचिव अशोक दीक्षित के खिलाफ क्षेत्र के व्यापारियों ने भ्रष्टाचार की शिकायतें की थी। इसी वर्ष मई माह में सदर बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने कटरा थाने में अशोक दीक्षित के खिलाफ रेप का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके अलावा विधायक रोशनलाल वर्मा ने तिलहर मंडी परिषद के प्रभारी सचिव अशोक दीक्षित के खिलाफ अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए पत्र में जिक्र किया था। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेन्द्र प्रताप सिंह ने विधायक के पत्र का संज्ञान लेते हुए तिलहर मंडी परिषद के प्रभारी सचिव अशोक दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनको बदायूं भेज दिया। इस संबंध में विधायक रोशनलाल वर्मा ने बताया कि भाजपा सरकार में किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नही करने दिया जायेगा। तिलहर के प्रभारी मंडी सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं जिसपर उन्होंने मंडी परिषद के निदेशक को पत्र लिखकर शिकायत की थी।

विरासत वृक्षों को हेरिजेटज ट्रीज के रूप संरक्षित किया जा रहा

लखनऊ। हमारे आस-पास व्यक्तियों यथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रोपित वृक्ष ऐसे वृक्ष जिनसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रंता सेनानियों को फांसी में लटका दिया। जनभावना, श्रृद्धा व हमारी स्मृतियों से जुड़े वृक्ष पाए जाते हैं। हमारे कई मुहल्लों व ग्रामों के नाम वृक्षों पर रखे गए है तथा कई स्थनों की पहचान, परिचय वहाँ स्थित विशालकाय, प्राचीन वृक्ष से ही होती है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, विशिष्टजनों से धार्मिक परम्पराओं व मान्यताओं से जुड़े, विलुप्त हो रहे एवं 100 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को चिन्हित कर विरासत वृक्षों को (हेरिजेटज ट्रीज) के रूप संरक्षित किया जा रहा है। विरासत वृक्षों के अन्तर्गत स्थानिक वृक्ष (इनडेमिक प्लान्ट), प्रथम बार पहचानी गई वृक्ष प्रजाति, ऐसे वृक्ष जिनका पुनर्जनन नहीं हो रहा है, मातृ वृक्ष (मदर ट्री) एवं विशिष्ट विशिष्टताओं वाले वृक्षों का चयन भी विरासत वृक्षों के रूप में अब तक बरगद, पाकड़, पीपल, नीम, अर्रू व साल सहित विभिन्न प्रजातियों के 261 वृक्षों का चयन विरासत वृक्ष के रूप में किया गया है। वन क्षेत्र के बाहर स्थानीय निकायों एवं वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा विरासत वृक्षों का चिन्हांकन किया जा रहा है।

डीज़ल पेट्रोल के बढ़ते मूल्य पर कांग्रेसियों ने किया तांगे पर मोटरसाइकिल रखकर विरोध प्रदर्शन

शाहजहाँपुर । वृहस्पतिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जनपद शाहजहांपुर के कांग्रेस जन ज़िला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन पर दोपहर ग्यारह बजे एकत्र हुए और डीज़ल, पेट्रोल के दामों में लगातार की जा रही बेतहाशा ब्रद्धि के विरोध में ज़ोरदार प्रदर्शन किया सभी कांग्रेस जनों ने पहले एक खड़े ट्रक में धक्का लगाया फिर जिलाध्यक्ष श्री रजनीश कुमार गुप्ता 卐मुन्ना卐 और शहर अध्यक्ष श्री तस्लीम अली के संयुक्त नेतृत्व में तांगों पर मोटरसाइकिलें रखकर एवं रिक्शे पर बैठकर टाउन हाल होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए थाना सदर स्थित पेट्रोल पम्प पहुंचे फिर चौराहे पर ज़ोरदार धरना प्रदर्शन किया इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद हुआ, फिर पंखी चौराहे से निकलकर सरदार पटेल हिन्दू इंटर कॉलेज होते हुए शहीद पार्क पहुंचे और वहीं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर संयुक्त अध्यक्षों ने धरने को समाप्त करने की घोषणा की इस दौरान जिलाध्यक्ष श्री रजनीश ने कहा कि सरकार ने रोज़ रोज़ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर किसानों की आमजन की कमर तोड़ दी है इस कुठाराघात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, ऐसा इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि डीज़ल जिसका प्रयोग कृषि कार्य में सबसे ज्यादा होता है जो हमारे देश का आधार है उसे पेट्रोल से भी ज्यादा कीमत में कर दिया है जो बेहद निंदनीय है उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है इस दौरान मुख्य रूप से कृष्ण विनोद मिश्रा, सावित्री शर्मा, ममता सिंह ,मनोज त्रिपाठी, विश्व दीप अवस्थी ,फुरकान अहमद कुरैशी, अनूप वर्मा ,अटल बिहारी वाजपेई, ब्रजेश गुप्ता, गौरव त्रिवेदी, हस्सू खां, अखिलेश पाल, सैयद फहीम उल कदर, अदीब अहमद फरमान ,शावेज़, और अतित कुमार गुप्ता बागी सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे !

मुख्यमंत्री ने 01 लाख से अधिक मेडिकल स्क्रीनिंग टीम के गठन की कार्यवाही को तत्काल अन्तिम रूप देने के दिए निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 01 लाख से अधिक मेडिकल स्क्रीनिंग टीम के गठन की कार्यवाही को तत्काल अन्तिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए समस्त आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मेडिकल स्क्रीनिंग टीम को इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जाए। टीम के सदस्यों के लिए मास्क, ग्लव्स तथा सेनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सैम्पल लिए जाएं। 11 जनपदों में नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियों तथा वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ शासन स्तर से निरंतर संवाद रखा जाए। इनके फीडबैक के आधार पर आवश्यकतानुसार जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने समस्त जनपदों के लिए नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को आवंटित जिले के कोविड एवं नॉन कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं का नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्षणरहित कोरोना संक्रमित को कोविड हॉस्पिटल में रखा जाए। ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण किया जाए। अस्वस्थ होने की दशा में इन्हें उपचार हेतु तत्काल कोविड अस्पताल में भर्ती किया जाए। चिकित्साकर्मियों को मेडिकल इंफेक्शन से सुरक्षित रखने के लिए इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर जारी रखे जाएं। पुलिस व पी0ए0सी0 कर्मियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी सावधानियां बरती जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अस्पतालों में भर्ती रोगियों के परिजनों से संवाद रखते हुए उन्हें रोगी के स्वास्थ्य की प्रतिदिन जानकारी दी जाए। रोगियों को सुपाच्य भोजन तथा पीने के लिए गुनगुना पानी उपलब्ध कराया जाए। कोविड-19 के उपचार कार्य में '108', '102', ए0एल0एस0 तथा निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस का उपयोग किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन उपलब्ध रहे। एम्बुलेंस में पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में सेनिटाइजेशन का कार्य निरंतर जारी रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगारों, श्रमिकों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की कार्यवाई निरंतर जारी रखी जाए। कामगारों, श्रमिकों को आवश्यकतानुसार बैंक से ऋण उपलब्ध कराने में एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा मदद की जाए। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण, प्राकृतिक संतुलन एवं जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि 25 करोड़ वृक्षारोपण के लिए कार्ययोजना तैयार करते हुए स्थलों को चिन्हित कर लिया जाए। लक्ष्यों के आवंटन के अनुसार कार्यों का अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाए।

69000 शिक्षक भर्ती मामला

एजी करेंगे बहस, 07 जुलाई को सुनवाई

लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में अजय कुमार ओझा तथा उदयभान चौधरी की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका की सुनवाई अब 07 जुलाई 2020 को होगी, सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में प्रदेश सरकार तथा परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के महाधिवक्ता स्वयं बहस करेंगे जो आज उपलब्ध नहीं हैं, अतः 07 जुलाई को सुनवाई रखी जाये. इस पर याचीगण की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर ने आपत्ति जाहिर की कि इस मामले में सरकार अनुचित तेजी दिखा रही है और इतने दिनों में प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करेगी. सरकारी अधिवक्ता ने मौखिक रूप से कहा कि इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, सरकारी अधिवक्ता एवं नूतन की दलील सुनकर जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने सुनवाई हेतु 07 जुलाई नियत किया, याचिका में कहा गया है कि 06 जनवरी 2019 को इस परीक्षा के बाद पेपर लीक के संबंध में एसटीएफ तथा केंद्र अधीक्षकों द्वारा प्रदेश के कई स्थानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिससे व्यापक स्तर पर पर्चा लीक होने की बात साबित होती है. आज भी एसटीएफ इस केस में विवेचना कर रहा है, अतः याचिका में परीक्षा को निरस्त करने तथा एसटीएफ पर सरकार के दवाब में काम करने के आधार पर सीबीआई जाँच कराये जाने की प्रार्थना की गयी है।

लालजी टंडन की हालत में हुआ सुधार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल मे भर्ती मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत मे लगातार तेजी से सुधार हो रहा है। अस्पताल के निदेशक राकेश कपूर ने बुधवार को कहा कि टंडन को नली के जरिए भोजन दिया जा रहा है। अब उनका लीवर, किडनी और दिल ठीक से काम कर रहा है। टंडन को पेशाब आने मे दिक्कत और बुखार के कारण 11 जून को मेदांता अस्पताल मे दाखिल कराया गया था। पेशाब मे संक्रमण पाये जाने के बाद उनका इलाज शुरू किया गया। जांच मे उनके लीवर मे भी दिक्कत पाई गई। राकेश कपूर ने कहा कि तेजी से सुधार को देखते हुए उन्हें जल्द ही छुट्टी दी जा सकती है। टंडन को फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। टंडन का हाल जानने राज्यपाल आंनदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत अन्य नेता आ चुके हैं।

लॉकडाउन में कासा सामाजिक संस्था प्रवासी मजदूरों और वंचित परिवारों की मदद कर रहा

लखनऊ। कासा सामाजिक संस्था द्वारा कोविड-19 संकट में लाकडाउन से प्रभावित उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के 294 ग्राम पंचायतों के 434121 जरूरतमंद परिवारों को मदद की गई। कोरोना वायरस के कारण होने वाले इस वर्तमान संकट के मद्देनजर, सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई, तो जहाँ एक तरफकोविड 19 मामलों को नियंत्रित करने की चुनौती थी, वहीं दूसरी तरफइस लाकॅडाउन के कारण वंचित समुदायों के सामने भोजन सहित न्यूनतम जरूरतों की चुनौतियाँ पैदा हो गईं। इस संकट के समय में कासा द्वारा अपने साथी सामाजिक संगठनों के साथ परिस्थितियों का आंकलन करते हुए जरूरतमंद परिवारों को मदद मुहैया कराने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। इस अभियान में समुदायिक के लोगों और युवाओं को शामिल किया गया। इस क्रम में सबसे पहला काम कोरोना वायरस के लक्षण और बचाव के बारे में समुदाय के बीच जागरूकता पर केन्द्रित किया गया। जिससे समुदाय को इस बीमारी से बचाया जा सके। अपने गांवों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों की सूची तैयार कर उनके स्वास्थ्य जाँच के लिए जिला प्रशासन से सम्पर्क किया गया। इसके साथ ही जिन प्रवासी श्रमिकों के पास राशन कार्ड नहीं था, उनकी सूची तैयार कर ग्राम प्रधान और जिला प्रशासन को दिया गया। कई क्षेत्रों में समुदाय ने जैविक सेनेटाइजर तैयार किया। इस दौरान युवाओं ने समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हाथ से पोस्टर बनाये और स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महराजगंज, कुशीनगर, देवारिया, सिद्धार्थनगर, बहराइच, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, और बुन्देलखण्ड के झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, जिलों के 294 ग्राम पंचायतों में यह अभियान चलाया गया। इस सभी जिलों में बैनर, पोस्टर और हैंडबिल के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कोविद-19 वायरस के सम्बंध में समुदायों में पर्चा वितरित किया गया तथा जागरूकता के लिए यात्रा आयोजित की गई। जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन, मास्क, साबुन और सैनिटाइजर वितरित किया गया। स्थानीय स्तर पर और जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ संपर्क किया गया और समुदाय के जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक राहत सामग्री दी गई, तथा समुदाय के नेताओं द्वारा डोर टू डोर लोगों से बात की गई और युवाओं द्वारा तैयार किए गए हस्तनिर्मित पोस्टर लगाये गये तथा दीवार पेंटिंग भी की गई। ललितपुर जिले के मड़ावरा ब्लाक में स्थानीय योगदान के माध्यम से समुदाय के वंचित परिवारों को पका हुआ भोजन दिया गया और राशन वितरित किया गया तथा गांवों में सेनेटाइजर का छिड़काव किया गया। समुदायिक संगठन के महिला सदस्यों को जिले के अधिकारियों द्वारा मास्क तैयार करने का अवसर दिया गया, जिससे उन्हें संकट के समय आय का एक स्त्रोत प्राप्त हो सके। इसी तरह जौनपुर जिले के मछलीशहर और बक्सा ब्लॉक के 8 ग्राम पंचायतों में प्रवासी श्रमिकों और मैला ढोने वाले परिवारों को राशन किट और वश किट वितरित किया गया, इसके साथ ही समुदाय आधारित संगठन की महिला स्वयंसेवकों द्वारा समुदायों में वितरण के लिए 1500 मास्क तैयार किया गया।

कासा सामाजिक संस्था के प्रमुख कमल कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान इस अभियान द्वारा 16 जिलों के 294 ग्राम पंचायतों के 434121 परिवारों को कवर किया गया तथा उन्हें भोजन, राशन, साबुन, सेनेटाइजर और मास्क की मदद की गई। उन्होंने आगे की कार्ययोजना के बारे में बताया कि प्रवासी मजदूरों की सूची तैयार कर और जिला प्रशासन के साथ बातचीत करके, उन्हें राशन कार्ड मुहैया कराया जायेगा और सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुए मनरेगा के तहत कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके, इसके लिए प्रशासन के साथ बातचीत करके योजना बनाई जायेगी।

रेलवे लखनऊ मंडल के वित्त विभाग ने दर्शाई विशिष्ट एवं सुनियोजित कार्य प्रणाली

लखनऊ। सर्वविदित है कि जीवन की समस्त व्यवस्थायें एवं आवश्यकतायें मुद्रा की धुरी पर स्थित हैं प्वित्त की समुचित उपलब्धता तथा कुशल प्रबंधन प्रत्येक परिस्थिति में विजय के द्वार खोल देती है अतः इसी अकाट्य सत्य का अनुसरण करते हुए उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के वित्त विभाग द्वारा लॉक डाउन अवधि में अपनी विशिष्ट कार्य प्रणाली द्वारा जहाँ एक ओर समस्त वित्त प्रबंधन के कार्य को अत्यंत सुगमतापूर्वक संपन्न किया गया वहीँ दूसरी ओर आपदा प्रबंधन हेतु समय समय पर मंडल द्वारा किये जाने वाले प्रयासों ,कार्यकलापों एवं गतिविधियों के सुगम संचालन को ध्यान में रखते हुए यथासमय वित्त प्रबंधन के कार्य को सुगमतापूर्वक संपन्न किया गया, इस संक्रमण काल में महामारी के विरुद्ध मंडल द्वारा किये गए प्रयासों के अंतर्गत विभाग द्वारा लगभग रु0 17.96 करोड़ की धनराशि को चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता एवं कोविड-19 सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं की त्वरित आपूर्ति हेतु उपलब्ध कराया गया साथ ही मंडल के अंतर्गत कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का माह मार्च-20 के 01 दिन के वेतन की धनराशि के योगदान को समायोजित करके यथासमय प्रधानमन्त्री राहत कोष में सहायता हेतु प्रदान किया गया साथ ही लॉक डाउन की अवधि में मंडल की शीर्ष पंक्ति में रहकर रेलसेवा करने वाले तथा घर पर ही रहकर रेलकार्य करने वाले समस्त कर्मियों को प्रदान किये जाने वाले माह मार्च ,अप्रैल एवं मई 20 के वेतन का भुगतान समयनुसार किया गया साथ ही इस अवधि में सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों के समस्त देय धनराशि को म-च्च्व् के माध्यम से सम्बंधित कर्मचारी के खाते में सीधे समायोजित करने का प्रावधान किया गया द्य उल्लेखनीय है की ब्व्टप्व्-19 को ध्यान में रखते हुए श्रमिक गाडियों के सुगम संचालन एवं अन्य वांछित आवश्कताओ को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु वित्त विभाग ने मंडल पर यात्रा समाप्त करने वाली तथा आवागमन करने वाली समस्त श्रमिक विशेष गाडियों हेतु समुचित वित्त प्रबंधन करने की दिशा में अत्यंत सराहनीय प्रयास किये एवं इस अवधि विशेष में मंडल द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विभिन्न रेल कार्यो की दिशा में आय एवं व्यय की मदों को निर्धारित समय पर उपलब्ध करा कर रेल कार्यो की निरंतरता को एक नया आयाम प्रदान किया द्य विदित है की लॉकडाउन की अवधि में यात्री यातायात पर विराम लगा होने के कारण इस अवधि के आरक्षित टिकटों की धन वापसी को दृष्टिगत रखते हुए मंडल के वित्त विभाग द्वारा यथा समय वित्त प्रबंध करके वाणिज्य विभाग को उपलब्ध कराया गया।

सम्पादकीय

मनरेगा : रोजी-रोटी का सहारा

कोरोना के चलते पूरे भारत में ग्रामीण संकट गहरा रहा है काम की मांग बढ़ती जा रही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मांग को पूरा करने के लिए आगामी बजट में जोर-शोर से देखी जा रही हैं। ग्रामीण गरीबी से लड़ने के लिए सरकार के शस्त्रागार में यह एकमात्र गोला-बारूद हो सकता है। हालांकि, योजना को कर्कश, बेकार और अप्रभावी रूप हमने भूतकाल में देखे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण नौकरियों की मासिक मांग 20 मई तक 3.95 करोड़ पर एक नई ऊंचाई को छू गई थी, और महीने के अंत तक 4 करोड़ को पार कर गई। इस साल मई में चारों ओर बड़े पैमाने पर नौकरी के नुकसान का संकेत आया, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में, जहां लाखों कर्मचारी अचानक तालाबंदी के कारण बेरोजगार हो गए हैं। मनरेगा के तहत काम मांगने वालों की अधिक संख्या हताशा के कारण है। शहरी श्रमिकों में से अधिकांश घर चले गए हैं और उनके पास कोई काम नहीं है इसलिए वे योजना के तहत नौकरी मांग रहे हैं। डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि मई-जून में मनरेगा की नौकरियों की मांग में बढ़ोतरी हुई है आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जिन राज्यों में श्रमिकों का रिवर्स माइग्रेशन देखा गया है, उनमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है। मनरेगा की नौकरियों की बढ़ती मांग ग्रामीण बेरोजगारी की पुष्टि करती है। ग्रामीण घरों में कम से कम 100 दिन की गारंटी वाला रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2006 में मगनरेगा की शुरुआत की गई थी। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित सबसे बड़ी योजना है। यह सामुदायिक कार्यों के माध्यम से सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक श्रम कार्यक्रम है। यह जीवन के अधिकार के संवैधानिक सिद्धांत को मजबूत करने के लिए एक विधायी तंत्र है। इसने ग्रामीण घरेलू आय बढ़ाने में मदद की है। इसने पिछले एक दशक में न केवल भूजल तालिका को बढ़ाने में मदद की है, बल्कि कृषि उत्पादकता, मुख्य रूप से अनाज और सब्जियां और चारा उगाने और बढ़ाने में मदद की हैं। खेत तालाबों और खोदे गए कुओं सहित जल संरक्षण के उपायों ने गरीबों के जीवन में बदलाव किया है।इसने गरीब घरों की जरूरत के अनुसार बकरी, मुर्गी और मवेशी शेड उपलब्ध कराया है, सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण किया है, जिन्होंने ग्रामीण आय में वृद्धि की है। आधार के आने से मनरेगा भुगतान में फायदा देखना को मिला है। लेकिन फिरभी कुछ समस्याएं है जो सुलझाने की जरूरत है देरी से मुआवजे का भुगतान करने से बचने के लिए प्रणाली विकसित हो क्योंकि मजदूरी के भुगतान में देरी जानबूझकर दबा दी जाती है।18 राज्यों में मगनरेगा मजदूरी दरों को राज्यों की न्यूनतम कृषि मजदूरी दरों से कम रखा गया है। काम की बढ़ती मांग के कारण योजना धन से बाहर चल रही है। कई राज्यों में सूखे और बाढ़ के कारण काम की मांग बढ़ गई है। राज्यों में मनरेगा मजदूरी में डाटा की असमानता है। कृषि न्यूनतम मजदूरी लगभग सभी राज्यों में मनरेगा मजदूरी से अधिक है।मनरेगा को सरकार की अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ग्रीन इंडिया पहल, स्वच्छ भारत अभियान आदि। मनरेगा के तहत कार्यों को पूरा करने में देरी हुई है और परियोजनाओं का निरीक्षण अनियमित रहा है। इसके अलावा, मनरेगा के तहत काम की गुणवत्ता मुख्य मुद्दा है। स्थानीय स्तर के सामाजिक आडिट, फंडिंग और परिणामों की ट्रैकिंग पर ध्यान देने के माध्यम से मनरेगा के मांग-संचालित पहलुओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर गाँव में सार्वजनिक काम शुरू हो। कार्यस्थल पर काम करने वाले श्रमिकों को बिना किसी देरी के तुरंत काम प्रदान किया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों को निश्चित रूप से वापस लौटे और प्रवासी श्रमिकों की खोज करनी चाहिए और जॉब कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता वाले लोगों की मदद करनी चाहिए। पारदर्शिता और सरपंचों की जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि मनरेगा की परियोजनाओं को गाँव-स्तर पर ही सही, न कि ग्राम पंचायत स्तर पर ही ट्रैक किया जाए.जहां आज सब कुछ बंद है वहां ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना रोजी-रोटी का सहारा बनकर उभरी है गांव में प्रवासियों के लिए रोजगार के रास्ते खुले है और लोगों को भूखे पेट सोना नहीं पड़ रहा।

स्वदेशी में है जमीं-आस्मां का फर्क

स्वदेशी व आत्मनिर्भरता के हमारे नारे करीब डेढ़ सौ साल पुराने हो चुके हैं- खासकर स्वदेशी। इसकी अवधारणा ने गांधीजी के भारत के राजनैतिक परिदृश्य पर उभरने के पूर्व ही जड़ें जमा ली थीं पर गांधीजी ने ही इसे देश की आजादी के साथ जोड़कर उसे जनता का न केवल आर्थिक हथियार बनाया था, बल्कि इसे नैतिक आयाम भी प्रदान किया था।

अब जो फिर से स्वदेशी का नारा बुलंद किया गया है, वह गांधी की स्वदेशी की अवधारणा से काफी अलग और दूर है। इसलिये इसे सफल बनाने के लिये कहीं ज्यादा बड़े प्रयासों की जरूरत होगी। स्वदेशी का पहला नारा बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने बंगदर्शन के साल 1872 में विज्ञान सभा का प्रस्ताव रखते हुए दिया था। उन्होंने कहा था- श्जो विज्ञान स्वदेशी होने पर हमारा दास होता, वह विदेशी होने के कारण हमारा प्रभु बन बैठा है। हम लोग दिन-ब-दिन साधनहीन होते जा रहे हैं। 1874 में भोलानाथ चन्द्र ने भी शम्भुचन्द्र मुखोपाध्याय द्वारा प्रवर्तित श्मुखर्जीज़ा मैग्जीनश् में स्वदेशी का नारा दिया था। उन्होंने स्वदेशी को एक अस्त्र बताते हुए लिखा था- इस अस्त्र को अपनाना कोई अपराध नहीं है। आईए, हम सब लोग यह संकल्प करें कि विदेशी वस्तु नहीं खरीदेंगे। युगांतकारी पत्रिका श्सरस्वतीश् के जुलाई, 1903 के अंक में श्स्वदेशी वस्त्र का स्वीकारश् शीर्षक से एक कविता छपी थी, जिसकी प्रारंभिक पंक्तियां थीं- श्विदेशी वस्त्र हम क्यों ले रहे हैं?, वृथा धन देश का क्यों दे रहे हैं? न सूझै है अरे भारत भिखारी! गई है हाय तेरी बुद्धि मारी!श् हालांकि उसमें रचनाकार का नाम नहीं था परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि वह कविता स्वयं पत्रिका के सम्पादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही थी। वर्ष 1905 के बंग-भंग के विरोध में हुए जनजागरण से स्वदेशी आन्दोलन को नया जीवन प्राप्त हुआ था। 1911 के दिल्ली दरबार में बंग-भंग रद्द तो कर दिया गया, पर स्वदेशी आन्दोलन नहीं रुका। अपितु वह स्वतन्त्रता आन्दोलन का अभिन्न अंग बन गया।महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पहले वह देश के सफलतम आन्दोलनों में से एक था। कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अरविन्द घोष, और लाला लाजपत राय जैसे महापुरुषों ने स्वदेशी आन्दोलन को गति दी थी। गांधीजी ने इसे देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन से यह कहकर जोड़ा था कि श्स्वदेशी स्वराज की आत्माश् है। भारत के स्वतंत्रता के इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण आन्दोलन बना था जो रणनीतिक था, तो दर्शन पर आधारित भीय क्योंकि इसका लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करते हुए भारत में बनी वस्तुओं का अधिकाधिक इस्तेमाल कर साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक क्षति पहुंचाना और गरीब भारतीयों का आर्थिक सशक्तिकरण करना था। यह ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने और भारत की समग्र आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए अपनाई जाने वाली समग्र प्रणाली थी। गांधी ने इसे विस्तार दिया। वर्ष 1921 की जुलाई व अगस्त में देश भर में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। इन आंदोलनों ने भारतीय जनता को इतना हौसला दिया कि अखबारों में इसके बाकायदे विज्ञापन छापे जाने लगे, लोग दूकानों के बाहर पिकेटिंग करते, बेंतें खाते। तिलकजी का कोलकोता पहुंचने पर 30 हजार लोगों ने स्वागत किया और इससे प्रेरित होकर श्वंदे मातरम्श् व श्युगांतरश् जैसे अखबार निकले। और तो और, टैगोर ने प्रेरित होकर श्शिवाजीश् शीर्षक से एक लंबी कविता तक लिख डाली।

अब बहिष्कार के इस नये नारे की बात करें तो पहली बात तो यह है कि वह एकांगी है। एक देश की वस्तुओं का बहिष्कार कर अगर आप वह सामान दूसरे देश से मंगाकर उपभोग में लाते हैं तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता क्योंकि आप उस मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुए। आप विकल्प के रूप में जिस दूसरे देश से उसकी आपूर्ति करते हैं तो वैसी ही स्थिति आने पर आप उस देश का भी बहिष्कार कर तीसरा देश देखेंगेय अथवा संभव है कि पहले वाले देश से अगर तब तक रिश्ते सुधर गये तो आप फिर उससे व्यापारिक संबंध जोड़ लेंगे। दरअसल श्स्वदेशीश् का नया नारा लद्दाख की असफलता से लोगों का ध्यान बंटाने का वैसा ही तरीका है, जैसे कोरोना के प्रबंधन में मिली असफलता से श्आत्मनिर्भरताश् का नारा ऊपजा था। यह दुर्भाग्य ही है कि जब भी ऐसा कुछ होता है, तो विदेशी आंदोलन ध्यान में आता है। 1991 के दौरान जब भारत में वैश्विक उदार आर्थिक प्रणाली लाई गई तो भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनैतिक जवाब के रूप में यही नारा लेकर स्वदेशी जागरण मंच के रूप में आते हैं जो बाद में चुपचाप अपनी सरकारों के विदेशी निवेश व उत्पादों के प्रति लगाव को देखते रहते हैं- बगैर हस्तक्षेप के। इसी नारे को लेकर कभी राजीव दीक्षित तो कभी रामदेव बाबा आते हैं।

वे भी अपने सीमित उद्देश्य पूरा कर चले जाते हैं। नारा वहीं का वहीं रह जाता है। आज जिस चीन के कारण लोगों को फिर से स्वदेशी की याद दिलाई जा रही है, उसी देश के प्रमुख से हमारे प्रधानमंत्री ने एक दर्जन बार से अधिक मुलाकातें पिछले छह वर्षों में की हैं। उद्देश्य? वहां के निवेशकों और उद्योग-धंधों व व्यवसायों को आमंत्रित करना। उनकी मेहनत रंग भी लाई है। देश में काम कर रहे स्टार्ट अपों में से ज्यादातर में चीनी पैसा है। स्नेपडील में तो 5320 करोड़ रुपये से भी ज्यादा (हालांकि वह चीनी कंपनी नहीं है)। स्विगी, ओला, जोमैटो, पेटीएम, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट आदि में भी चीन ने खूब पैसे लगाये और कमाये हैं। जिस चीन का बहिष्कार करने की बात हो रही है उसने पिछले दो वर्षों में ही करीब 85 हजार करोड़ रुपए का हमारे यहां निवेश किया है। मोदीजी के राज्य गुजरात में तो सर्वाधिक है। यह तो सच है कि नई आर्थिक नीति पीवी नरसिंह राव के वक्त लाई गई पर उन्होंने अधिकतर क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा रखी थी। अब तो अनेक क्षेत्रों में इसका प्रतिशत काफी बढ़ा दिया गया है। बैंक खोलने से लेकर चीन को व्यवसाय चलाने संबंधी अनेक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। चूंकि प्रेम व युद्ध की तरह व्यवसाय में सारा कुछ जायज होने लगा है, ऐसे कदमों से हमारी सरकारें ही देशी उद्योगों को विदेशी निवेशकों के मुकाबले कठिन प्रतिस्पर्धा में ढकेल देती हैं। विदेशी निवेशक नवीनतम टेक्नालॉजी व भारी राशि के साथ आयेंगे जो देशी उद्योग-धंधों को मुकाबले से बाहर खदेड़ देंगे। संरक्षण और बाजार देने की बजाय हम उन्हें तबाह करने के रास्ते पर पहले ही धकेल चुके हैं। हमारे व्यवसाय जगत में वैदेशिक कंपनियों की भागीदारी व संलग्नता इतनी व्यापक व मजबूत हो चुकी है कि चाहे अमित शाह आपको चीनी माल के बहिष्कार के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हीं के पुत्र जय शाह (महासचिव) का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नुकसान की बिना पर एक चीनी प्रायोजक से करार तोड़ने से इंकार कर देता है। मोदी कहते थे कि साल में अगर हर व्यक्ति केवल दो जोड़ी खादी के कपड़े खरीदे तो यह सेक्टर निखर जायेगा। खादी उद्योग आज मौत की कगार पर है क्योंकि यह आह्वान करने वाले स्वयं ही ज्यादातर समय विदेशी वस्तुओं के साथ देखे जाते हैं।

एक ओर चीन का विरोध तो दूसरी ओर उसके भारत के निवेश को सुरक्षित व संवर्धित किया जाता रहेगा, ऋण भी लिये जाते रहेंगे, सड़कों के ठेके भी देंगे, तो कैसे चीनी वस्तुओं का बहिष्कार होगा? आखिरकार, आत्मनिर्भरता ही नहीं, राष्ट्रीय स्वाभिमान, पुरुषार्थ व मानवीय गौरव की अवधारणाएं भी स्वदेशी के साथ नत्थी जो हैंय और वही हमारी अक्षय आर्थिक आजादी का फार्मूला भी है। ऐसी सरकार व पार्टी के लिये इस अवधारणा को स्वीकारना एवं पचा पाना कदाचित असंभव है जो जीएसटी को देश की दूसरी आजादी मानें। स्वदेशी व आत्मनिर्भरता के नये नारे पहले की अवधारणा के विपरीत नफरत, द्वेष, प्रतिस्पर्धा और सीमित उद्देश्यों को लेकर लाये गये हैं। ये अक्सर शासकों की सनक, झक या गुस्से से ऊपजते हैं जबकि स्वदेशी का क्रियान्वयन बेहद रणनीतिक कुशलता के साथ तो होना ही चाहिये, उसके नैतिक व देश के पुरुषार्थ जैसे पक्षों को भी संजोया जाना चाहिये। गांधीजी के जिस स्वदेशी आंदोलन के कारण ग्रेट ब्रिटेन के कई मिल मजदूर बेकार हो गये थे, उन्हीं की बस्ती में वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के दौरान रुके भी थे- यह इस आंदोलन की रूहानी ऊंचाई है, जिसे प्राप्त करना हर किसी के लिये कतई आसान नहीं है।

महिलाओं को सहारा देने वाली ही आज खुद बेसहारा

181 वुमन हेल्पलाइन में कार्मिकों की मांगों पर वर्कर्स फ्रंट ने अपर श्रमायुक्त लखनऊ को दिया पत्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सन 2015 में शुरू की गई आशा ज्योति वूमेन हेल्पलाइन 181 में काम करने वाले 351 जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं उन्हें आज सरकार ने बेसहारा कर दिया है. उन महिलाओं को और कर्मचारियों को पिछले एक साल से वेतन का भुगतान नहीं किया गया और कोविड-19 के समय जब बिना संसाधन और सरकारी सुविधाओं के उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया उसके एवज में 5 जून को उन्हें काम से हटाने का नोटिस सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश की सेवा प्रदाता कंपनी जीवीके द्वारा दे दिया गया है. इस संबंध में आज वर्कर्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर कपूर के नेतृत्व में आशा ज्योति महिला हेल्पलाइन में काम करने वाली महिलाओं ने अपर श्रमायुक्त लखनऊ को पत्रक दिया. पत्रक में मांग की गई कि सेवा प्रदाता कंपनी की मनमर्जीपूर्ण और विधि के विरुद्ध की गई छंटनी की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और एक साल से बकाए वेतन का तत्काल भुगतान किया जाए. गौरतलब हो कि यह वूमेन हेल्पलाइन के द्वारा विधवा, पति त्यागता, कम उम्र की बच्चियों की शादी के विरुद्ध, बलात्कार पीड़ित और अन्य रूप से उत्पीड़ित की गई महिलाओं की सहायता के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने आशा ज्योति वूमेन हेल्पलाइन का गठन किया था और 181 मोबाइल नंबर के जरिए पूरे प्रदेश में ऐसी महिलाओं की मदद की जाती थी. इसके लिए सरकार ने सिकंदराबाद की जीवीके रिसर्च कंपनी के साथ समझौता किया था और समझौता में यह तय किया था यह काम 5 साल तक चलेगा और कार्य का अग्रिम भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा. लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तब से इन महिलाओं को आमतौर पर वेतन भुगतान में दिक्कत आने लगी और हद यह हो गई कि पिछले एक साल से तो भुगतान ही रोक दिया गया है. सेवा प्रदाता कंपनी का कहना है कि यदि सरकार द्वारा उसे भुगतान नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में वह कैसे भुगतान कर पाएगी. इस संबंध में अपर श्रमायुक्त को वर्कर फ्रंट द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया के ठेका मजदूर कानून और समयबद्ध वेतन भुगतान अधिनियम के तहत मुख्य नियोजक भी वेतन भुगतान के लिजवाबदेह हैं इसलिए निदेशक, महिला एवं बाल विकास को भी पत्र भेजकर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए. पत्रक में यह भी कहा गया कि कोरोना के संकटकालीन दौर में जब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार यह कहा जा रहा है कि किसी को भी सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा और इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा भी आदेश दिया गया है.तब ऐसी स्थिति में लॉकडाउन के दौरान सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा अपने कार्मिकों को काम से हटाने का आदेश देना विधि के विरुद्ध, मनमर्जी पूर्ण तो है ही साथ ही आपराधिक कृत्य है. इसलिए महामारी अधिनियम के तहत इस कंपनी के खिलाफविधिक कार्यवाही कराएं जाना भी न्यायोचित होगा.

प्रतिनिधि मंडल की बातों को सुनने के बाद अपर श्रमायुक्त ने तत्काल सेवा नियोजन कंपनी और निदेशक महिला विकास महिला एवं बाल विकास को नोटिस जारी करके जुलाई में वार्ता के लिए आदेशित किया है. वार्ता में रूचि, दिव्या, मीनू, सीमा, दिप्ती आदि लोग रहे।

उप्र में कोरोना संक्रमण के दोगुना होने की गति 18.14 दिवसः कांग्रेस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू एवं नेता विधायक दल आराधना मिश्रा मोना का ने संयुक्त बयान में कहा पिछले कई महीनों से कोरोना महामारी देश में फैली हुई है। उप्र भी भयंकर रूप में आतंकित है। शासन के प्रयासों के बावजूद भी स्थिति ऐसी बन गई है कि जितना यथाशक्ति प्रयास कर सकते हैं हम सहायता कर रहे हैं। इस समय हम ये नहीं समझते कि किसी प्रकार की राजनीति या स्थिति की अवहेलना की जाए उप्र के 4 जिले देश में कोरोना के मरीजों की सर्वाधिक मृत्युदर वाले 15 जिलों में शामिल हैं। झाँसी, मेरठ, आगरा और एटा। उप्र की आबादी को देखते हुए, प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर होने वाले

टेस्ट की संख्या देखें तो उप्र अपने से छोटे कई राज्यों की तुलना में कम टेस्ट कर रहा है। उप्र में कोरोना संक्रमण के दोगुना होने की गति 18.14 दिवस है। यह देश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित पाँच राज्यों में से तीसरे नं पर है। देश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में उप्र 5वें स्थान पर है। हमने जब आगरा में पूछताछ की तब ये पता चला कि अब तक आगरा में 1150 लोग कोरोना पॉजीटिव निकले और उनमें से 84 लोगों की मृत्यु हो गई। इन मृतकों में 28 लोगों का निधन अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटों में ही हो गया।हम यही बताना चाहते हैं कि इस महामारी से लड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास ही नहीं बल्कि जो भी आवश्यक निदान हैं और जो भी व्यवस्थाएं हैं उन पर अवश्य दृष्टि रखना चाहिए। यदि कोई जिलाधिकारी यह समझता है कि हम गलत कहना चाह रहे हैं या हम किसी की भावना को अन्य दृष्टि में ले जाना चाह रहे हैं तो उस जिलाधिकारी की समझ और सामर्थ्य ठीक नहीं है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जिलाधिकारी आगरा को प्रियंका गांधी जी के ट्वीट से मतलब न होकर जो आगरा में पीड़ित लोग हैं उनकी चिकित्सा पर पूर्ण विचार और कार्य करना चाहिए। यदि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किसी भी तरह की मदद चाहिए तो हम तत्पर हैं।

परिवहन निगम की बसों की दुर्घटनाओं की संख्या में 18 प्रतिशत की कमी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में घटित दुर्घटनाओं के सापेक्ष तुलनात्मक विवरण है,अवधि दुर्घटनाओं की कुल संख्या फैटल दुर्घटनाओं की संख्या मृतक की संख्या घायलों की संख्या,वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 648 307 390 802,गत वित्तीय वर्ष 2018-19 748 376 484 806,अन्तर-कमी,अधिकता (-)100 (-)69 (-)94 (-)4 अन्तर कमी,अधिकता का प्रतिशत -13 प्रतिशत -18 प्रतिशत -19 प्रतिशत 0.49 प्रतिशत तुलनात्मक विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के सापेक्ष घटित दुर्घटनाओं में 13 प्रतिशत की कमी, फैटल दुर्घटनाओं की संख्या में 18 प्रतिशत की कमी, मृतकों की संख्या में 19 प्रतिशत की कमी हुई है एवं घायलों की संख्या में 0.49 प्रतिशत की कमी हुई है।परिवहन निगम में दुर्घटनाओं की रोकथाम के प्रयासों के अन्तर्गत चालकों को प्रशिक्षण, स्वस्थ्य एवं नेत्र परीक्षण तथा काउन्सिलिंग आदि की प्रक्रिया निरन्तर की जाती है। सेवा आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित चालक के विश्राम की निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। दैनिक रूप से बसों को मार्ग पर भेजने से पूर्व उनकी 13 बिन्दुओं यथा बस में एसएलडी,वीटीएस,अग्निशमन यन्त्र एवं फ्स्टएड किट की क्रियाशीलता एवं अन्य वांछित तकनीकी जांच करायी जाती है। बस के प्रस्थान से पूर्व सम्बन्धित चालक का ब्रेथ एनालाईजर के द्वारा ब्रीथिंग का परीक्षण किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त, मार्ग पर संचालित बसों के चालकों का औचक रूप से ब्रेथ एनालाईजर के माध्यम से परीक्षण भी किया जाता है। कोविड-19 के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन अवधि में संचालित आपातकालीन सेवाओं में तथा अनलाक-1 में सामान्य संचालन में भी उपरोक्त सुरक्षात्मक उपाय नियमित रूप से सुनिश्चित कराये जा रहे है। परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने वाले सम्मानित यात्रियों को विश्वसनीय, आरामदायक, सुलभ एवं सुरक्षित सेवा प्रदान करने के प्रति संकल्पित हो हम उक्त दिशा में वांछित कार्यवाही करते हुये निरन्तर प्रयत्नशील है।

आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवाओं को समाप्त किये जाने पर नाराजगी

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के निदेशक ने 16 मई को समस्त परिषदीय कार्यालयों और समस्त मण्डी समितियों में संविदा, आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवाओं को 30 जून से समाप्त किये जाने का आदेश दिये हैं। इस आदेश से कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। महामंत्री ने कहा कि इस कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी में अल्प वेतन भोगी कर्मियों की सेवा समाप्ति का आदेश उचित नही है। इस निर्णय से प्रदेश के 1200 कर्मचारी प्रभावित होंगे जो विगत पांच से छह वर्षों से अपनी सेवायें पूर्ण इमानदारी व निष्ठा से कर रहे हैं। परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि अल्प वेतन भोगी कर्मियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्मिक विभाग द्वारा निर्मित स्थाई नीति को मंत्रिपरिषद से अनुमोदन हेतु निर्देशित व मण्डी परिषद द्वारा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त अथवा कही समायोजन करवाने की कृपा करें।

प्रदेश में कानून व्यवस्था अंतिम सांस ले रही: अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अंतिम सांस ले रही है। बेरोजगारी से परेशान और हताश लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नौजवान ठगा महसूस कर रहे हैं। जनता किससे राहत की उम्मीद करे जबकि भाजपा सरकार लोगों का खून निचोड़ने में लगी है। कोरोना संकट से तो जिंदगी ऐसे ही बेपटरी हो चली है, ऊपर से सरकार की गलत नीतियों के चलते कामकाज, पढ़ाई, व्यापार के सभी रास्ते अवरूद्ध हैं। औरैया के दिबियापुर में जिला जज की गाड़ी पर बदमाशों ने हमलाकर दिया। जब न्यायाधीश सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या हाल होगा? उन्नाव के पुरवा क्षेत्र में पुलिस कर्मी पर दो बदमाशों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। उनकी बाइक तोड़ दी। खून से लथपथ सिपाही अस्पताल पहुंचाए गए। लखीमपुर में सत्ता से संरक्षण प्राप्त सीओ ने अपने ड्राइवर पर पिस्तौल तान दी। सीओ पर कड़ी कार्यवाही के बजाय उसे ट्रैफिक में भेजकर मामला दबा दिया गया। प्रदेश की भाजपा सरकार से युवाओं को नाउम्मीदी के अलावा और कुछ नहीं मिला। सन् 2017 से सन् 2020 तक एक भी नौकरी में भर्ती नहीं हुई। हर नौकरी भ्रष्टाचार की शिकायतों से भरी रही। इन्वेस्टमेंट मीट में अरबों रूपए फूंक कर एक सुई का कारखाना तक भाजपा सरकार नहीं लगवा सकी। फिर भी करोड़ों को नौकरी देने का झूठा प्रचार कर युवाओं को धोखा दिया जा रहा है।

व्यापारियों के दोपहिया वाहनों के चालान ना काटे जाएं -सचिन बाथम

शाहजहाँपुर । उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले आज गोविंदगंज इकाई व सदर बाजार इकाई के व्यापारियों ने एसपी सिटी श्री संजय कुमार व सिओ सिटी प्रवीण कुमार यादव से गुहार लगाई कि बाजार में व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान पर दो पहिया वाहन की आवश्यकता होती है जिससे वें अपना बैंक का कार्य अपने दुकान का कार्य वह गोदाम से माल लाने व ले जाने का कार्य करते हैं दोपहिया वाहन वर्तमान समय में अति आवश्यक है परंतु पुलिस द्वारा दुकान पर खड़े दोपहिया वाहन का भी चालान काट दिया जा रहा है जिस कारण बाजार से ग्राहक गायब हो गया है । व्यापारियों ने गुहार लगाई कि बाजार में आप चार पहिया वाहन पर प्रतिबंध लगा दिए हमें कोई आपत्ति नहीं परंतु दोपहिया वाहनों का आवागमन जारी रहने दे। साथ ही महानगर अध्यक्ष श्री सचिन बाथम जी ने बताया कि नगर निगम की पुल के

नीचे पार्किंग पर कुछ दुकानदार पल्ली लगाकर दुकान लगाए हैं जिस कारण पार्किंग नहीं हो पा रही है कृपया चार पहिया वाहनों की पार्किंग पुल के नीचे कराई जाए तथा व्यापारी के दो पहिया वाहनों का चालान ना काटा जाए जिससे व्यापारी के व्यापार करने में आसानी हो सके । इस पर एसपी सिटी ने आश्वासन दिया कि जल्दी आपकी समस्या का निराकरण करा दिया जाएगा इस अवसर पर गोविंद गंज के अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह सदर बाजार के अध्यक्ष श्री पंकज टंडन बहादुरगंज के अध्यक्ष श्री कंचन गुप्ता हनी सिंह हरमीत सिंह इंद्रजीत सिंह लवी बग्गा लकी बग्गा आदि व्यापारी मौजूद रहे ।

कोतवाली क्षेत्र के मऊ गांव में फूटा कोरोना बम

महाराजगंज रायबरेली-कोतवाली क्षेत्र के मऊ गांव में गुरुवार को कोरोना बम फूटते हुए एक साथ 5 लोगो की रिपोर्ट कोरोना पाजिटिव आई है। 5 लोगो के कोरोना पाजिटिव की खबर आने से क्षेत्र में हड़कम्प का माहौल है। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मऊ गर्वी गांव को हाट स्पाट घोषित कर बैरिकेटिंग शुरू कर दी है। बताते चले की 14 जून को कोतवाली क्षेत्र के मऊ गर्वी गांव निवासिनी एवं सीएम हेल्पलाइन लखनऊ में कार्यरत लड़की की कोरोना रिपोर्ट लखनऊ में पाजिटिव आई थी। मालूम को की 10 जून को यह अपने घर मऊ आई थी और 12 जून को वापस लखनऊ गई थी। लड़की की कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आने पर प्रशासन द्वारा उसके घर के 10 परिजनो में से सात को फिरोज गाधी पालीटेक्निक रायबरेली में क्वारनटीन कराया था जिसमे से 5 लोगो की रिपोर्ट बुधवार को पाजिटिव आई है। कोतवाल अरुण कुमार सिंह ने बताया की सीएम हेल्पलाइन में कार्यरत लड़की के 5 परिजनो की रिपोर्ट पाजिटिव आई है जिससें मऊ गांव स्थित मऊ गर्वी इलाके को हाट स्पाट घोषित किया गया है यहाँ लड़की के माता पिता व दादी पूर्व से होम क्वारनटीन है जिनकी सैम्प्लिग स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की जानी है। फिलहाल एक साथ 5 लोगो की रिपोर्ट कोरोना पाजिटिव आने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।

डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर देश की जनता और किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही केंद्र सरकार

सपा नेताओं ने डीजल-पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को लेकर दिया ज्ञापन

हरदोई। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव संजय कश्यप, समाजवादी छात्र सभा के नि राष्ट्रीय सचिव मुकुल सिंह आशा, यूथ ब्रिगेड नि जिला अध्यक्ष रामज्ञान गुप्ता ने देश में बढ़ रहे डीजल-पेट्रोल के दामों को वापस लेने व प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में रोजगार देने को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा ।ज्ञापन के माध्यम से समाजवादी नेताओं ने मांग की कि देश में फैली भीषण महामारी कोरोना वायरस के चलते देश का आम जनमानस किसान, मध्यमवर्गीय लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है।वहीं देश की भाजपा की केंद्र सरकार लगातार 16 -17 दिनों से डीजल-पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी करती जा रही है।

शाहजहाँपुर । समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर खा कटरा से पूर्व विधायक राजेश यादव व जलालाबाद विधायक कुँवर शरदवीर सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को डीज़ल/पेट्रोल के दामो में वृद्धि प्रदेश की कानून व्यवस्था और जनहित के मुद्दों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौपा ।जिस पर जिलाअध्यक्ष तनवीर खा ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाकर देश की जनता और किसानों साथ सौतेला व्यवहार कर रही है

उन्होने कहा खरीफ की फसल की बुवाई और धान की रूपाई शुरू हो चुकी है किसानों को डीजल और खाद महंगे

होने से किसान परेशान है और लॉक डाउन के 70 दिन की अवधि में किसानों के ट्यूबबेल के 3 महीने के बिजली के बिलों को लगातार वसूला जा रहा है और बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे है जिससे किसान परेशान है प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है जनपद में अपराधियों के हौसले बुलंद है खुले आम थाना सिंधौली क्षेत्र में सपा कार्यकर्ता के बेटे की हत्या ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है पुलिस की कार्यशैली से आम लोगो का कानून व्यवस्था से भरोसा उठता जा रहा है श्री खा ने कहा कि प्राइवेट स्कूल संचालक मनमानी कर रहे है अभी स्कूल बंद होने पर अभिभावकों को तीन महीने की फीस कोर्स और ड्रेस खरीदने को बाध्य कर रहे है

जिस पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। जिलापूर्ति कार्यालय में बाबूओं की लापरवाही से राशनकार्डो में भारी त्रुटियां है किसी के यूनिट काट दिये गये है किसी के परिवार के सदस्य के नाम दर्ज नही है और जिनके राशन कार्ड नही बने है कार्यालय द्वारा कैम्प लगाकर इनको दुरुस्त कराया जाए। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेश,विधायक कुँवर शरदवीर सिंह यादव ,सैय्यद रिज़वान अहमद,डॉ0 नवनीत यादव,गायत्री वर्मा,कपिल वर्मा, उपेंद्र पाल सिंह,हफ़ीज़ अहमद अंसारी,मो0 आरिफ,परवेज़ अंसारी,तैय्यब खान,इमरान खान,विजय सिंह,सौमित्र यादव ,हिमाशु वाजपेयी, दिव्यांश कोविद,सौरभ यादव,अजीत यादव ,सादिक अंसारी,शुलभ यादव गुफरान खान,आनंद शुक्ला,इमरान अंसारी,रईस अहमद और सभी सम्मानित पदाधिकारीगण व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर साधा निशाना, राघवेंद्र सिंह व उनकी टीम ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

अक्षय मिश्र

आज लालगंज तहसील में उपजिलाधिकारी जी के माध्यम से राज्यपाल महोदय जी को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ज्ञापन दिया गया। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राघवेन्द्र सिंह पंकज के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकताओं ने तहसील पहुंच कर विरोध किया। व्यापारी, छात्र, किसान नौजवान परेशान हैं।17.दिन से ये लगातार बृद्धि हो रही है। केन्द्र में बैठी मोदी सरकार आम जनमानस को परेशान कर रही है। राघवेंद्र सिंह ने कहा जब कांग्रेस की सरकार थी तब पेट्रोल में यदि 10 पैसा भी बढ़ोतरी होती थी तब भाजपा के

नेता रोड़ पर हायतोबा मचा देते थे वो इस तरह से प्रदर्शन करते थे जैसे बहुत बड़ा संकट देश के ऊपर आ गया हो पर आज वर्तमान समय में भाजपा सरकार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रही है।कोरोना बीमारी में लोग रोजगार और सरकार के फैसले से परेशान हैं।और पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़कर सरकार जनता को पूरी तरह परेशान कर रही है। केन्द्र की मोदी सरकार की हर योजना विफल रही है। आये दिन किन्हीं कारणों से जनता को ही परेशान होना पड़ता है। सरकार पेट्रोल डीजल के दामों को कम कर के जनता को राहत पहुंचाये। नहीं 10.दिनो के अन्दर युवा कांग्रेस एक बड़े विशाल आन्दोलन के लिए बाध्य होगी। मुख्य रूप से उपस्थित युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, सरेनी विधानसभा अध्यक्ष हर्ष भदौरिया, हरचंदपुर विधानसभा अध्यक्ष नीरज मिश्रा,जिला प्रवक्ता कमल सिंह चौहान,जिला महासचिव सुमित यादव, लालगंज ब्लांक अध्यक्ष विशाल शर्मा उपाध्यक्ष भास्कर मिश्रा, उपाध्यक्ष आदर्श सिहं।हर्ष अग्रहरि, प्रशांत द्विदी, विवेक गुप्ता,मेराज कुरैशी। तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे।

सचिन की परछाई में खेलता रहा ये खिलाड़ी- गौतम गंभीर

नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ने पिछले कुछ हफ्तों में एक चैट शो में विभिन्न खिलाड़ियों और विषयों के बारे में अपने विचार और राय साझा की। इस बार गंभीर ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के देश के क्रिकेट पर प्रभाव के बारे में बताया। गंभीर ने कहा है कि राहुल द्रविड़ ने सचिन के साथ अपने करियर के लगभग सभी मैच खेले हैं, लेकिन उनका प्रभाव एक जैसा रहा है। टेस्ट क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ को बतौर कप्तानी सराहने वाले गौतम गंभीर ने स्टार स्पोर्ट के शो क्रिकेट कनेक्टेड में उनके क्रिकेटिंग करियर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, अगर आप राहुल द्रविड़ को एक क्रिकेटर के रूप में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपने उनसे टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करने के लिए कहा होता तो वे करते। उन्होंने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की और विकेट पर जमे रहने का काम किया।

गंभीर ने कहा, द्रविड़ ने मैच फिनिशर के रूप में बल्लेबाजी की, उन्होंने सब कुछ देखा। भारतीय क्रिकेट ने उनसे जो कहा या कप्तान के तौर पर उनसे जो पूछा गया उन्होंने वो किया। आप चाहते हैं कि वे किस तरह के रोल मॉडल हैं। मेरे करियर पर मुझे लगता है कि उनका बड़ा प्रभाव पड़ा है। सौरव गांगुली ने हमेशा अपने तेजतर्रार प्रदर्शन के कारण सफेद गेंद के क्रिकेट में बड़ा प्रभाव डाला है, लेकिन भारतीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ ने बहुत अधिक प्रभाव डाला, जो शायद किसी ने भी देखा हो।6 वनडे मैचों में देश की वनडे टीम की कप्तानी करने वाले गौतम गंभीर ने कहा है, आप वास्तव में सचिन तेंदुलकर जैसे किसी व्यक्ति के साथ उनके प्रभाव का मिलान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सचिन तेंदुलकर की परछाई में खेला। यहां तक दोनों का प्रभाव एक जैसा रहा। गंभीर के कहने के मायने ये थे कि जब मैदान पर सचिन तेंदुलकर होते तो दूसरा कोई खिलाड़ी उनको डोमिनेट नहीं कर सकता था। यही भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के साथ हुआ।

अब जुलाई में होगा T20 विश्व कप 2020 के भविष्य का फैसला

नई दिल्ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आइसीसी को इस साल ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित टी20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर फैसला लेना है। इससे पहले 10 जून को टी20 विश्व कप 2020 का भविष्य तय होना था, लेकिन इसे थोड़ा खिसका दिया। वहीं, जब गुरुवार को आइसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई तो इस पर फैसला नहीं किया गया और सूत्रों ने जानकारी दी कि टी20 विश्व कप का भविष्य जुलाई के मध्य में तय होगा। बता दें कि जुलाई के बीच में आइसीसी की वार्षिक बोर्ड बैठक होनी है। इसी बैठक में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर होने वाले टी20 विश्व कप पर फैसला होना है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ये संभव नहीं है कि 16 टीमों वाले इस इवेंट को आयोजित किया जा सके। वहीं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआइ भी आइसीसी के इस फैसले का इंतजार इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर कर रहा है। ICC बोर्ड के सदस्यों ने इस महीने में दूसरी बार गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुलाकात की, लेकिन अक्टूबर-नवंबर के लिए निर्धारित ञ्20 विश्व कप पर ज्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि इस मीटिंग में केवल चेयरमैन के चुनाव के लिए चर्चा के लिए समय दिया गया था। एक सूत्र ने कहा, आइसीसी अध्यक्ष की प्रक्रिया पर अच्छी चर्चा हुई और इसे अगले सप्ताह में अंतिम रूप दिया जा सकता है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के चेयरमैन कॉलिन ग्रेव्स बीसीसीआइ के पूर्व चेयरमैन और आइसीसी के मौजूदा बॉस शशांक मनोहर की जगह लेने की रेस में सबसे आगे हैं। यदि बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली चुनाव लड़ सकते हैं तो उन्हें बोर्ड के संविधान के अनुसार कूलिंग-ऑफ अवधि के लिए मजबूर किया जा सकता है। बीसीसीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर उस नियम में संशोधन करने की मांग की है, जिससे गांगुली पूरे तीन साल का कार्यकाल पूरा कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि महामारी के कारण इस साल विश्व कप के होने की संभावना नहीं है। वहीं, बीसीसीआइ उत्सुकता से एक स्थगन का इंतजार कर रहा है ताकि वह आइपीएल का आयोजन कर सके और 4000 करोड़ की डील को भुना सके। बीसीसीआइ के अधिकारियों का कहना है कि यहां तक कि प्रसारणकर्ता, जो दोनों टी20 प्रतियोगिताओं के लिए अधिकार रखते हैं, वे इस बात के लिए उत्सुक हैं कि आइपीएल इस साल एक विंडो को ढूंढता है।

वर्ल्ड कप 2019 फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड की टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोस टोलर को लगता है कि वनडे मैच के टाई होने के दुर्लभ मामले में विश्व कप की ट्रॉफी साझा करने वाली टीमें बुरा नहीं मानेंगी, क्योंकि उनका मानना है कि वनडे प्रारूप में सुपर ओवर जरूरत नहीं है। बता दें कि पिछले साल न्यूजीलैंड और मेजबान इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था, जो मुकाबला टाई रहा था। यहां तक कि सुपर ओवर भी टाई रहा था, लेकिन बाउंड्री काउंट के आधार पर इंग्लैंड को जीत मिली थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विश्व कप के फाइनल में विनियमन अवधि में मैच टाई और फिर बाद में सुपर ओवर के बाद न्यूजीलैंड के

खिलाफ इंग्लैंड को बाउंड्री काउंट के आधार पर विजेता घोषित किया था। इसके बाद दृष्टष्ट के इस नियम की काफी आलोचना हुई थी। हालांकि, बाद में उस नियम को बदल दिया गया। अब सेमीफाइनल और फाइनल मैट टाई होने पर सुपर ओवर तब तक होगा, जब तक कि एक टीम मैच नहीं जीत जाती।

ईएसपीएन क्रिकइंफो के हवाले से रोस टेलर ने कहा है, मैं अभी भी वनडे मैच में सुपर ओवर के खिलाफ हूं, मुझे लगता है कि एकदिवसीय क्रिकेट इतने लंबे समय से खेला जाता है कि मुझे टाई होने में कोई समस्या नहीं है। ञ्20 में ऐसा होना सही है। फुटबॉल या कुछ अन्य खेलों की तरह, उस जीत को पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वनडे मैच में सुपर ओवर की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आपके पास एक संयुक्त विजेता हो सकता है।एक दिवसीय खेल की लंबाई को देखते हुए, टेलर को लगता है कि टाई एक उचित परिणाम है। कीवी बल्लेबाज ने कहा है, विश्व कप के दौरान मैं वास्तव में अच्छा खेल कहने के लिए अंपायरों के पास गया, मुझे यह भी नहीं पता था कि एक सुपर ओवर होगा। एक टाई एक टाई है, मुझे लगता है कि आपके पास यह तर्क किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 100 ओवरों के मैच में बराबरी पर ठहरते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है।

मेरी जिंदगी में एक ऐतिहासिक इवेंट- सचिन तेंदुलकर

नई दिल्ली। 1983 विश्व कप जीत के बारे में याद करते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने गुरुवार को कहा कि यह मेरे जीवन में एक ऐतिहासिक घटना थी। गुरुवार 25 जून 2020 को भारत और कपिल देव एंड कंपनी ने वर्ल्ड कप 1983 की जीत की 37वीं वर्षगांठ मनाई। गुरुवार को ज्यादातर भारतीय क्रिकेटरों ने अपने-अपने अंदाज में वर्ल्ड कप 1983 की जीत को याद किया, जिसमें पूर्व क्रिकेटर भी शामिल थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर अकाउंट पर वर्ल्ड कप 1983 को लेकर ट्वीट किया और लिखा है, कई लोगों के लिए वर्ल्ड कप 1983 का फाइनल कुछ और रहा हो, लेकिन मेरे जीवन में यह एक ऐतिहासिक घटना थी। फिर भी मैं अपने दोस्तों को याद करता हूं और बीएस संधू की एपिक डिलीवरी से लेकर कपिल पाजी की कैच तक सभी विकेट का जश्न मनाता हूं। हम कूद गए और प्रत्येक विकेट के पतन का जश्न मनाया! वो क्या शाम थी।

बता दें कि भारतीय टीम ने 25 जून 1983 को लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था और भारत ने दो बार की विश्व चैंपियन टीम वेस्टइंडीज को 43 रन से हराया था। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने कैरेबियाई टीम को 140 रन पर ढेर कर दिया था और अपना पहला विश्व कप का खिताब जीता था। भारत ने दूसरा खिताब 28 साल के बाद साल 2011 में एमएस धौनी की कप्तानी में श्रीलंका को हराकर जीता था। विश्व कप का खिताब जीतने के बाद टीम के कप्तान

कपिल देव ने लॉर्ड्स की बालकनी में जो ट्रॉफी उठाई थी, वो तस्वीर आज भी क्रिकेट प्रेमियों के जहन में जिंदा है। फाइनल मैच में मोहिंदर अमरनाथ प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, जिन्होंने पहले 26 रन की दमदार पारी खेली और फिर तीन विकेट लेकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी थी। भारत ने इससे पहले 1975 और 1979 का भी वर्ल्ड कप खेला था, लेकिन सेमीफाइनल तक का सफर भी तय नहीं किया था।

कपिल देव ने किया खुलासा

नई दिल्ली। 25 जून 2020 को भारत ने साल 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीतने की 37वीं वर्षगांठ मनाई तो ऐसा लगा, जैसे ये अभी की बात है कि भारत ने कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन इस बात को करीब चार दशक हो गए। यही कारण है कि जब भारतीय क्रिकेट के किसी ऐतिहासिक लम्हे की बात आती है तो उसमें 1983 की विश्व कप जीत को याद किया जाता है। इसी जीत को याद करते हुए उस टीम के कप्तान कपिल देव ने गुरुवार को कहा कि उस जीत ने देश में बड़ा अंतर पैदा किया था.

फिल्मों में बिना किसी कनेक्शन से बॉलीवुड एक्टर बने सिद्धार्थ मल्होत्रा

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कई हिट फिल्मों में काम किया है। फिल्म स्टूडेंट ऑफ ईयर से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। एक्टर ने कहा कि बॉलीवुड में कैरियर बनाने के लिए मुंबई आना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि परिवार के साथ से उनकी यह यात्रा थोड़ी आसान हो गयी। सिद्धार्थ से जब सवाल किया गया था कि उनके मुंबई आने के फैसले का परिवार ने कैसे समर्थन किया तो उन्होंने कहा कि, मुझे याद है कि जब मैं मुंबई आया था तब मैं 21 साल का था और यहां पर मैं अकेले रह रहा था और इसके बाद मैंने जॉइंट फैमिली की खूब तारीफ की थी। दरअसल मैं खुद जॉइंट फैमिली में रहता था जहां कई सारे लोग एक साथ रहते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा कि, मुझे याद है जब मैं अपने माता-पिता से बात कर रहा था तो उन्हें कहा था कि आखिर हम फोन रखते हुए लव यू मां, लव यू डैड क्यों नहीं कहते। दरअसल हम पंजाबी परिवारों में ऐसा कल्चर नहीं है कोई बाहर जाकर इतनी दूर अकेले रहे। मुझे याद है जब मैं अपने पिता के साथ बैठा हुआ था तो मैंने उन्हें कहा था जब भी मैं जाऊंगा तो आप गुडबाय के साथ यह भी कहेंगे कि आप मुझे से प्यार करते हैं और उन्होंने जवाब दिया श्या या, बेशक। अभिनेता ने आगे कहा कि, उन्होंने मुझे मारा और यह काफी मजेदार था। इसी बीच कई ऐसे पिता होते हैं जिनके 21 साल के बच्चे दूसरे शहरों में रहते हैं और वह हमेशा अपने पिता से फोन रखने से पहले पूछते हैं कि क्या वह उनसे प्यार करते हैं। मुझे एहसास हुआ कि जब मैं एक अभिनेता बनने के लिए मुंबई आया था, तो यह आसान नहीं था और मुझे लगा कि आपके माता-पिता ने आपको सिखाया है कि आप क्या कर रहे हैं।

सिद्धार्थ ने 18 साल की उम्र में एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने फिल्मकार करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में 2010 की फिल्म ष्माई नेम इज खान में काम किया, जौहर की 2012 में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ थी ईयर से डेब्यू किया था। सिद्धार्थ ने हसी तो फसी, ब्रदर्स, एक विलेन और कपूर एंड संस और बार-बार देखो जैसी फिल्मों में काम किया है। अभिनेता ने कहा कि उसके माता-पिता नहीं जानते थे कि वह बड़ा होकर अभिनेता बनना चाहता है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था जब मैं एक युवा था और फिल्मों में बिना कोई कनेक्शन हुए दिल्ली से बॉलीवुड अभिनेता बनना संभव था। वे मुझे एक अभिनेता के रूप में आकार नहीं दे रहे थे, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए मैं कहूंगा। और मेरा मतलब है कि यह अत्यंत विनम्रता के साथ है और यह नहीं कह रहा हूं कि मैं एक आदर्श उदाहरण हूं, लेकिन सिर्फ यह कहने के लिए कि कुछ बुनियादी गुण हैं, मुझे लगता है कि मुझे अपने परिवार से विरासत में मिला है और यही मैं लोगों को दे रहा हूं। अभिनेता सोचता है कि समाज में बहुत सारे मुद्दे कठोर परवरिश से उपजा है। सिद्धार्थ ने कहा कि, जब भी लोग देश के भीतर विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा या सुरक्षा के साथ शुरू करते हैं, तो यह कुछ ऐसा है जिसे समाज को ठीक करना है और पहले लड़कों को ठीक करने से उपजा है।

आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने कहा-एक दिन उनके भी बच्चे होंगे

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की इस तरह मौत से फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस शौक में हैं। अभिनेता ने मुंबई बांद्रा अपने घर में 14 जून को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुशांत की मौत के बाद लोगों ने फिर से नेपोटिज्म का मुद्दा उठा दिया है और सेलेब्स जैसे करण जौहर, आलिया भट्ट, सोनम कपूर आदि इनपर आरोप लगाया जा रहा की उन्होंने इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत को आउटसाइडर महसूस कराया। अब आलिया की मां सोनी राजदान ने चल रही भाई-भतीजावाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज जो लोग इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं क्या वह अपने बच्चों को समर्थन नहीं करेंगे अगर वो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहएंगे। निर्देशक हंसल मेहता के ट्वीट से यह पूरी चर्चा शुरू हुई। फिल्म मेकर हंसल मेहता ने हाल ही में ट्वीट करके कहा, नेपोटिज्म की बहस को और बड़ा होना चाहिए। मेरे बेटे को मेरी वजह से दरवाजे के भीतर कदम रखने दिया और क्यों नहीं, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ काम का अहम हिस्सा रहा, क्योंकि वो टैलेंटेड है, अनुशासन में रहता है, मेहनती है और उसमें भी मेरे जैसे गुण हैं।

हिना खान के ब्वॉयफ्रेंड ने सोनम कपूर की लगायी जमकर क्लास

इस समय नेपोटिज्म का मुद्दा फिल्म इंडस्ट्री में गरमाया हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री दो हिस्सों में इसे लेकर बंटी दिखाई दे रही है। इसका कई लोगों ने समर्थन किया है जबकि इसके खिलाफ भी कई लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। भाई-भतीजावाद का समर्थन हाल ही में सोनम कपूर ने किया। हालांकि इसके बाद सोनम कपूर की जमकर क्लास एक्ट्रेस हिना खान के बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल ने लगा दी। फिल्म जगत के कई बड़े निर्माता-निर्देशकों के साथ स्टार किड्स पर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का आरोप लगाया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी हस्तियों पर लोगों ने पिछले काफी दिनों से निशाना साधा है जो किसी फिल्मी परिवार से आते हैं। पिछले हफ्ते फादर्स डे के अवसर पर सोनम कपूर ने इसी बात का जवाब दिया था। सोनम कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा था, आज फादर्स डे पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी। मैं अपने पिता की बेटी हूं और हां मैं यहां उनकी वजह से हूं और मुझे बहुत कुछ खास मिला है। ये कोई बेइज्जती नहीं है, मेरे पिता ने मुझे ये सब देने के लिए बहुत मेहनत की है और ये मेरे कर्म ही हैं जिस कारण मैं कहां और किसके यहां पैदा हुई। मुझे उनकी बेटी होने

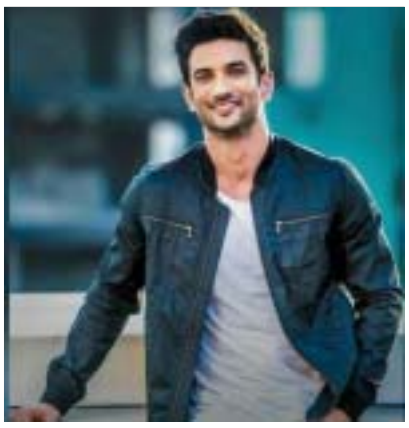

पर गर्व है। हिना खान के बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल ने सोनम कपूर के इस ट्वीट का जवाब दिया और लिखा, तो हर एक शख्स जिसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) और संपन्न न होने की वजह से मौका नहीं मिला और इस वक्त वे जहां हैं, वो उनके पिछले जन्म का कर्म है। इस तर्क से तो मैं आपकी अगली जिंदगी के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूं। पूरी इज्जत के साथ मैडम, मुझे आपसे कुछ बेहतर की उम्मीद थी।

बन जा तू मेरी रानी गाने पर थिरके थे सुशांत

सुशांत सिंह राजपूत के कई वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर चर्चा में हैं, जिनमें से एक वीडियो में वह एक इवेंट में डांस कर रहे हैं और सामने करीना कपूर बैठी हैं। इस वीडियो में सुशांत गुरु रंधावा के गाने पर बहुत ही शानदार डांस कर रहे हैं और करीना भी उनके डांस पर फिदा नजर आ रही हैं। किसी इवेंट में शूट हुए इस वीडियो में सामने करीना बैठी हैं और उनके आसपास कोई भी ऐक्ट्रेस नहीं हैं। सुशांत उनके सामने बन जा तू मेरी रानी गाना गाते हुए अपनी हथेली पर ताजमहल तक रखकर उन्हें दिखा देते हैं। सुशांत के इस परफॉर्मेंस से करीना काफी इम्प्रेस नजर आ रही हैं और फैन्स के लिए एक खूबसूरत याद हमेशा के लिए कैमरे में कैद हो गई। दरअसल इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो को गुरु रंधावा ने सुशांत को शुक्रिया कहते हुए शेयर किया है। उन्होंने इस पोस्ट में सुशांत के लिए लिखा है, भाई, हमने कभी साथ में काम नहीं किया और न ही कोई गाना किया, लेकिन बन जा तू मेरी रानी पर लिप सिंक के लिए आपको शुक्रिया। जहां भी आप हों हमेशा खुश रहें। बता दें कि सुशांत पिछले दिनों 14 जून को अपने घर पर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद से उनके डिप्रेशन की खबरें भी आने लगीं। एक तरफ जहां लोग उनके जाने के गम में डूबे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेपोटिजम बनाम आउटसाइडर्स को लेकर भी बहस छिड़ गई है।

अंदाज-ए-लखनऊ

एन0 आलम
सह संपादक
अंदाज ए लखनऊ
Mo : 9889966668

हसीब इदरीसी
विशेष संवाददाता
अंदाज ए लखनऊ
Mo : 9415249966

जगदीश कुमार गौतम
संवाददाता
अंदाज ए लखनऊ
Mo : 7985695040

अंदाज-ए-लखनऊ

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक अली हसन द्वारा सीता आफसेट हुसैनगंज लखनऊ से मुद्रित एवं 67/63 लालकुआं लखनऊ प्रकाशित।

सम्पादक : अली हसन
मो नं.-8604223368
RNI No.
UPHIN/2010/33668
Email Id.
andazelucknow@gmail.com

प्रबंध संपादक
फ़ैजान सिद्दीकी

उप सम्पादक
मनीष कुमार सच्चिदानंद

ब्यूरो चीफ : राहुल शुक्ला

छायाकार : सदफ हसन (शानू)

समस्त विवादों का निस्तारण लखनऊ न्यायलय के अधीन होगा।